

### प्रसाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I---खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

मं० 93]

नई दिल्ली, श्काबार, धाप्रैल 28, 1972/वैद्याल 8, 1894

No. 93]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रालग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

## RESOLUTION

New Delhi, the 28th April 1972

No. U-23018/1/72-WB.—The Government of India have decided to constitute a Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965. The composition and terms of reference of the Committee will be as follows:—

#### I. Composition

Chairman

Dr. B. K. Madan.

Members

- 1. Shri N. S. Bhat.
- 2. Shri Harish Mahindra.
- 3. Shri R. P. Bilimoria.

(683)

- 4. Shri G. Ramanujam.
- 5. Shri Satish Loomba.
- 6. Shri Mahesh Desai.
- 7. Dr. S. D. Punekar.

A Member Secretary will be appointed by Government.

## II. Terms of reference

To review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965, and to suggest suitable modifications to the scheme outlined therein and, in particular, to make recommendations on the following issues:—

- (i) Whether establishments (other than factories) employing less than 20 workers, may be covered by the Act and if so, upto what limit of employment? Should there be a separate formula for payment of bonus in these small establishments?
- (ii) Is there a case for raising the minimum bonus (4 per cent) and if so, to what level?
- (iii) Whether the present upper limit on payment of bonus and the system of 'set-on' and 'set-off' require any alteration and if so, on what lines?
- (iv) Whether the entire bonus payment should be related in some way to production/productivity in the undertaking?.
- (v) Whether the present minimum bonus of 4 per cent may continue but a provision be made for its being supplemented through suitable schemes of production/productivity?
- (vi) To consider and make recommendations on any connected/ancillary matters?

The Committee shall also make a careful assessment of the likely impact of its recommendations on the national economy before finalising them.

2. The Committee will be known as the BONUS REVIEW COMMITTEE and its headquarters will be located at Bombay. Correspondence intended for the Committee will be addressed for the present to the Chairman, Bonus Review Committee C/o the Department of Industries & Labour, Government of Maharashtra, Sachivalaya, Bombay.

#### ORDER

- (i) All State Governments and Union Territories.
- (ii) All Ministries of the Government of India and Planning Commission.
- (iii) All India Organisation of Employers and Workers.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

N. P. DUBE, Jt. Secy.

# श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रमग्रौर रोजगारविभाग)

## संकरुप

नई दिल्ली, 28 श्रप्रेल, 1972

संख्या यू०-23018/1/72-इस्त्यू० बी० :—बोनस भुगतान श्रिधिनियम, 1965 के प्रिचालन की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। सिमिति का गठन ग्रीर उसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

1. गठन

ग्रध्यभ

डा० बी० के० मदान

## सदस्य

- 1. श्री एन०एस० भट
- श्री हिरिश महिन्द्र
- श्री श्रार० पी० बिलिमोरिया
- 4. श्रीजी० रामानुजम
- श्री सतीम लूम्बा
- 6. श्री महेश देसाई
- 7. डा० एस० डी० पुनेकर

सरकार, एक सदस्य सचिव नियुक्त करेगी।

# II. विचारार्थं विषय

बोनस भुगतान श्रिधिनियम, 1965 के परिचालन की पुनरीक्षा करना श्रीर उसमें दी गई योजना की रूप रेखा के लिए उपयुक्त तरमीमों के बारे में मुझाव देना, श्रीर विषेश रूप से निम्नलिखित बाद-विषयों के संम्बन्ध में सिफारिशों करना:---

- (i) क्या ऐसा प्रतिष्ठान (कारखानों को छोड़ कर अन्य), जिनमें 20 से कम कर्मकार काम करते हैं, इस अधिनियम की परिधि में लाए जाएं और यदि हां, तो नियोजित व्य क्तियों की किस संख्या सीमा तक? क्या इन छोटे प्रतिष्ठानों में बोनस के भुगतान के लिए अलग सूत्र होना चाहिए।
- (ii) क्या न्यूनतम बोनस ( 4 प्रतिशत ) को बढ़ाने का कोई ग्रीचित्य है ग्रीर यदि है तो किस स्तर तक ?
- (iii) क्या बोनस भुगतान की वर्तमान उच्चतम सीमा और "सेट-म्रान" श्रीर "सेट-म्राफ" की प्रणाली में कोई परिर्वतन श्रपेक्षित है और यदि हां, तों किस परिपाटी पर ?
  - (iv) क्या सम्पूर्ण बोनस भुगतान का सम्बन्ध किसी प्रकारसे उपक्रम में उत्पादन /उत्पादिता से सम्बन्धित होना चाहिए ?
  - (V) क्या वर्तमान 4% का न्यूनतम बोनस देना जारी रहे परन्तु उचित उत्पादन/ उत्पादिता की योजनाश्रों द्वारा इसको श्रनुपुरक बनाने हेतु व्यवस्था की जाए?
  - (vi) किसी सम्बन्धित / ग्रनुषंगी मामलों पर विचार करना भ्रौर सिफारिश करना ।
  - सिमिति, भ्रपनी सिफारिशों को भ्रन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय अर्थं व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का सचेत मूल्यांकन भी करेगी!
- 3. समिति बोनस पुनरीक्षा समिति के नाम से जानी जायेगी श्रौर इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित होगा । समिति के लिए श्रभीष्ट पत्न-व्यवहार, फिलहाल, श्रष्ट्यक्ष, बोनस पुनरीक्षा समिति मार्फत उद्योग श्रौर श्रम विभाग महाराष्ट्र सरकार, सचिवालय, अम्बई से किया जाएगा ।

## मावेश

मादेग विया जाता है कि संक प की प्रतिलिधि निम्नलिखित को भेजी जाए:-

- (i) सभी राज्य सरकारों भार केन्द्र भासित क्षेत्र।
- (ii) भारत संस्कार के सभी मंत्रालय, योजना भाषोग ।
- (iii) नियोजकों मार श्रमिकों के म्राखा भारत संगठन।

यह भी भादेश विया जाता है कि संकल्प भारत के भ्रसाधारण राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एन० पी० दुबे, संयुक्त सचिव।